इकाई 28 राज्य और वैश्वीकरण

इकाई की रूपरेखा

28.0 उद्देश्य
28.1 परिचय
28.2 वैश्वीकरण और उसका संदर्भ
28.3 वैश्वीकरण के आयाम
28.3.1 आर्थिक वैश्वीकरण
28.3.2 राजनीतिक वैश्वीकरण
28.3.3 वैश्वीकरण एवं संस्कृति
28.4 राष्ट्र-राज्य और संप्रभुता
28.4.1 राज्य की परिभाषा और अर्थ
28.4.2 संप्रभुता
28.4.3 संप्रभुता को खतरा
28.5 वैश्वीकरण, राज्य और बहुराष्ट्रीय निगम
28.6 वैश्वीकरण, राज्य और क्षेत्रीयता
28.7 वैश्वीकरण और द्वैतवाद (Dualism)
28.7.1 विश्व का दो कैम्पों में विभाजन
28.8 एक मूल्यांकन
28.9 सारांश
28.10 कुछ उपयोगी संदर्भ
28.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

28.0 उद्देश्य

इस इकाई में राज्य-वैश्वीकरण अन्तरसंबंध (interface) की जाँच की गई है। इस इकाई से गुज़रने के बाद, आप निम्न के बारे में सक्षम हो जाएँगे :

- वैश्वीकरण के अर्थ को परिभाषित करना और उसकी विवेचना करना;
- वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों पर चर्चा करना;
- राज्य को परिभाषित करना और वैश्वीकरण के दृष्टिगत इसकी संप्रभुता के खतरों पर चर्चा करना;
- वैश्वीकरण के संदर्भ में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका पर चर्चा करना; तथा
- वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप राज्य के भविष्य पर टिप्पणी करना।

28.1 परिचय

वैश्वीकरण के संदर्भ में, आधुनिक राज्य भारी परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है। वैश्वीकरण प्रक्रियाओं से मुक्त अनेक बलों ने जनप्रिय कल्पना के केन्द्र के रूप में राज्य को प्रभावित किया है। राष्ट्र-राज्य विभिन्न स्तरों पर अपनी जनता के साथ अपने रिश्तों को पुनर्भाषित

करने के लिए सामने आए हैं। यद्यपि राज्य की संप्रभुता अभी भी महत्त्वपूर्ण है, यह स्थानीय स्तर पर विभाजन तथा भूमण्डलीय स्तर पर एकीकरण से बुरी तरह संकुचित हुई है।

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र-राज्य के विरूपण से क्षेत्रीय विरचनाओं की विशिष्टता पर निर्भर करते हुए विभिन्न रूप प्रगट होते हैं। इस पाठ में वैश्वीकरण के कई अर्थों और प्रथम भाग में राष्ट्र-राज्य हेतु इसके निहितार्थों पर विवेचना की गई है। बाद में, यह राष्ट्र-राज्य के विरूपण के विभिन्न आयामों को प्रकट करता है।

28.2 वैश्वीकरण और उसका संदर्भ

हमारे स्पष्टीकरण के लिए समान ध्वनि वाले शब्दों, वैश्वीकरण और भूमण्डलवाद को वर्गीकृत किया जाना चाहिए। वैश्वीकरण शब्द एक प्रक्रिया का हवाला देता है, जबकि भूमण्डलवाद ऐसा शब्द है जो विचारों, मूल्यों, प्रथाओं के ऐसे समूह का हवाला देता है जो आजकल वैश्वीकरण के नाम पर होने वाले परिवर्तनों की वचनबद्धता के समर्थन की माँग करता है। संक्षिप्त में, भूमण्डलवाद का अर्थ है, वैश्वीकरण के लिए एक विचारधारा अथवा उसको न्यायोचित ठहराने का फ्रेमवर्क।

आधुनिक युग के वैश्वीकरण की कुछ गलतफहमियों को दूर करना भी महत्त्वपूर्ण है। कुछ क्षेत्रों में, वैश्वीकरण को इससे सम्बन्धित भाव में इस प्रकार समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण अति प्राचीन समय से एक विचार और एक प्रथा के रूप में अस्तित्व में रहा है। यह जानकारी उचित ऐतिहासिक अर्थों में कम जान पड़ती है, क्योंकि यह विद्यमान संदर्भ में वैश्वीकरण की विशिष्टता को मान्यता प्रदान नहीं करती। वैश्वीकरण एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया से प्रकट हुआ है, जिसे पूँजीवादी विस्तार के पीछे दलीलों से ख़तरा बना हुआ है। यह भूमण्डलीय स्तर पर विशिष्ट प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में फलने-फूलने की माँग करता है। इससे भूमण्डलीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक भारी परिवर्तन हुए हैं। इसने एक या दो दशक के दौरान विश्व को पूरी तरह बदल दिया है।

अपने आर्थिक स्वरूप में वैश्वीकरण उन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक समेकित अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार का समर्थन करता है जो सामने आ रही हैं। यह सांस्कृतिक स्तर पर मूल्यों और संस्कृतियों का समांगीकरण (homogenisation) चाहता है और यह इस शब्द के राजनीतिक अर्थ में राष्ट्र-राज्य संप्रभुता सत्ता को हाशिए पर लाने अथवा कम करने के लिए भूमण्डलीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रति योगदान करता है। अन्तर्विरोध के तौर पर, वैश्वीकरण स्थानीय स्तर पर विविधता और विभाजन को भी सही मानता है। एक चारित्रिक लक्षण के रूप में भूमण्डलीय स्तर पर सार्वभौमिक और स्थानीय स्तर पर विभाजन वैश्वीकरण को जितना समांगी बनाता है, उतना ही विरोधाभासी बना देता है।

प्रत्यक्षतः दो विरोधाभासी प्रवृत्तियाँ हैं, जिन्हें विद्यमान भूमण्डलीकृत होने वाले विश्व मे देखा जा सकता है। प्रथम, राज्य क्षेत्रीय व्यापार और राजनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने की दौड़ में अपनी संप्रभुता को छोड़ते प्रतीत हो रहे हैं। दूसरे, विद्यमान राज्यों के भीतर स्वतंत्रता के कुछ उपायों पर दत्तचित्त होकर विभिन्न समूह अधिक संप्रभुता के लिए उत्तेजित हो रहे हैं। क्या विश्व अधिक समेकित हो रहा है अथवा इसके और अधिक टुकड़े हो रहे हैं? क्या हम और अधिक अन्तरराष्ट्रीय अथवा और अधिक स्थानीय हो रहे हैं? सभी मामलों में उत्तर स्पष्टतः स्वीकृति में मिलेगा। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार करार (NAFTA), एकमात्र यूरोपीयन बाज़ार और नवोद्भूत बहुपार्श्वीय एजेन्सी, विश्व व्यापार संगठन (WTO) सभी और अधिक समेकन के प्रति उठने वाले कदम हैं। भूमण्डलवाद के प्रति अन्तरराष्ट्रीय

हलचल अप्रशाम्य है। उपभोक्तावादी पूँजीवाद हमेशा विस्तार करने वाले बाज़ारों तथा सामान एवं सेवाओं का उत्पादन और उनका वितरण करने वाले हमेशा अधिकाधिक दक्ष तरीकों की अपेक्षा करता है। संक्रामी कम्पनियाँ सस्ते श्रम और कच्चे माल तथा संसाधित सामग्री के लिए अपनी तलाश में राष्ट्रीय सीमाओं के परिगमन के तरीके खोजने के लिए अधिकाधिक निपुण होती जा रही हैं।

इसी प्रकार, दक्षिण एशिया अथवा विश्व के अन्य क्षेत्रों में प्रजातीय, जाति, वर्ग, लिंग, जनजातीय और पारिस्थितिकीय समूह विद्यमान राज्यों के भीतर अधिक स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्थानीय दावे वास्तव में भूमण्डलीय कारण बन चुके हैं। सांस्कृतिक तौर पर, व्यष्टियों अथवा समूहों के लिए राष्ट्रीय पहचान का विचार प्रजातीय, क्षेत्रीय, जाति और धार्मिक पहचान की किलेबन्दी के पक्ष में तेज़ी से समाप्त होता जा रहा है।

बोध प्रश्न 1

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिए इकाई का अन्त देखें।

1) वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

28.3 वैश्वीकरण के आयाम

28.3.1 आर्थिक वैश्वीकरण

आज वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? चालू संदर्भ में, आर्थिक रूप से बात करने पर इसका अर्थ है मूल्यों, उत्पादों, वेतनों, ब्याज दरों और लाभों का समांगीकरण जिससे विश्व में सभी बराबर हो जाएँ। मुक्त बाज़ार, पारदर्शिता और लचीलेपन के बहाने तथाकथित *''इलैक्ट्रौनिकी हर्ड''* में देशों में और देशों से बाहर विशाल पूँजी राशियाँ पाश्चात्य देशों के राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए हस्तान्तरित होती हैं; जिससे विदेशी पूँजी आए तथा आज और कल की प्रौद्योगिकी का लाभ मिल सके।

28.3.2 राजनीतिक वैश्वीकरण

राजनीतिक शब्दों में, वैश्वीकरण का अर्थ है राष्ट्र-राज्य को इस तरीके से अभिलेखबद्ध (reorder) करना जो भूमण्डलीय एकता के अनुकूल हो। राष्ट्र-राज्यों की संप्रभुता की उम्मीद ही भूमण्डलीय स्तर की संप्रभुता के पश्चात् की जाती है। एक भूमण्डलीय राज्य व्यवस्था ही वांछित लक्ष्य माना जा सकता है। विश्व के वैश्वीकरण की प्रक्रिया में राष्ट्र-राज्य को हाशिए पर रखना सबसे बड़ी चुनौती है।

विश्व का वैश्वीकरण विधियों और विनियमनों की एक जटिल व्यवस्था द्वारा समर्थन प्राप्त है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और अन्य अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ

(IFIs) के नियामक क्षेत्र, गैट (GATT) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) विश्वभर में समान नीतियाँ, बाध्यताएँ और प्रतिबन्ध लागू करने के लिए एक नए विश्व शासन के रूप में तेज़ी से उभर रहे हैं। ये संस्थाएँ इस व्यवस्था को पूर्ण बनाने में निर्णायक हैं, जिससे व्यष्टि राष्ट्र-राज्यों को आबद्ध रहना है। इस प्रक्रिया का अन्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिक आयाम यह है कि राष्ट्रीय सरकारों पर अपने कानूनों को बदलने के लिए निरन्तर दबाव डाला जा रहा है, जिससे वे भूमण्डलीय शासन की उभरती व्यवस्था में अधिक स्पर्द्धात्मक हो सकें। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक अथवा विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं के नियामक क्षेत्रों को कमज़ोर राष्ट्र-राज्यों की आपत्तियों से कभी-कभार फर्क पड़ता है।

28.3.3 वैश्वीकरण एवं संस्कृति

वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझने में अन्य मुख्य क्षेत्र संस्कृति है। अपने मौलिक रूप में वैश्वीकरण का अर्थ मूल्यों का सार्वभौमीकरण भी है। मूल्यों का सार्वभौमीकरण सार्वभौमिक मूल्यों के अनुसार बदलते हुए लिया जाना चाहिए। मूल्यों के सार्वभौमिकीकरण में पूर्वकल्पित है कि एक निश्चित प्रकार की भूमण्डलीय व्यवस्था हो, जिसके प्रति बदले हुए राष्ट्रों, क्षेत्रों और स्थानों के सभी मूल्यों, प्रथाओं और परम्पराओं में बदलाव किया जाना चाहिए। वैश्वीकरण मूल्यों और संस्कृतियों के निरपेक्ष समांगीकरण की माँग करता है। सांस्कृतिक भूमण्लीकरण निरन्तर स्थानीय और राष्ट्रीय संस्कृतियों को मुख्यतः पश्चिम के आधिपत्य वाली भूमण्डलीय संस्कृति के साथ समेकन करने की माँग करता है। जब हम आर्थिक वैश्वीकरण के साथ सांस्कृतिक वैश्वीकरण पर दृष्टिपात करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि पूँजीवादी बाज़ार का विस्तार स्थानीय संस्कृतियों के भूमण्डलीय बदलाव की सहूलियत से स्थानीय बाज़ारों के समेकन पर लटका हुआ है/निर्भर है।

एक प्रसिद्ध समाजवादी, ऐंथानी गिड्डन्स महसूस करते हैं कि विश्व पूँजीवाद, उद्योगीकरण और आधुनिक राष्ट्र-राज्यों के संदर्भ में संगठनात्मक समूह भूमण्डलीय नेटवर्क का सार्वभौमीकरण करते हैं और समय-स्थान फासले को भी बढ़ा देते हैं, जिससे स्थानीय-भूमण्डलीय अन्तरसंबंध एक जटिल समस्या बन जाता है। ''तब वैश्वीकरण को विश्वव्यापी सामाजिक सम्बन्धों में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे दूरस्थ स्थल इस प्रकार जुड़ जाते हैं, ताकि स्थानीय घटनाएँ, कई मील दूर की घटनाएँ अथवा उसके प्रतिकूल नज़र आएँ''।

सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में वैश्वीकरण विश्व के सिकुड़ने और कुल मिलाकर सम्पूर्ण विश्व की चेतना के विस्तार का हवाला देता है। सूचना युग के उत्थान को भूमण्डल के आरपार संस्कृतिकरण प्रक्रिया की सहवर्ती घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। वैश्वीकरण के सभी आयाम पर्याप्त रूप से निम्न लक्षण सम्पन्न हैं – *''सामग्री आदान-प्रदान स्थानीय होते हैं, राजनीतिक आदान-प्रदान अन्तरराष्ट्रीय होते हैं तथा सांकेतिक आदान-प्रदान भूमंडलीय होते हैं।''*

बोध प्रश्न 2

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिये अंत में देखें।

1) आर्थिक अथवा राजनीतिक वैश्वीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) वैश्वीकरण-संस्कृति अन्तरसंबंध की जाँच करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

28.4 राष्ट्र-राज्य और संप्रभुता

आधुनिक युग में राष्ट्र-राज्य की राजनीतिक शक्ति, सम्पन्नता के आधार को समझना और उसके सापेक्षतः संक्षिप्त इतिहास पर चर्चा करना महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्र-राज्य का उन नागरिकों और शासन के रूप में वर्णन किया जाता है, जो भौगोलिक रूप से विशिष्ट सीमाओं के भीतर कार्य करते हैं। इस संयोजन को अभिनिश्चित करने के लिए राष्ट्र-राज्य को अपने नागरिकों की तरफ से स्वतःचैतन्य विश्वास की आवश्यकता है, जो सामूहिक रूप से देश की प्रदत्त जनसंख्या के मात्र ढेर/गिनती की तुलना में अधिक शक्तिपूर्ण है। राष्ट्र-राज्य नागरिक का प्रतीक है, उसे पूर्णतः संशक्तता के साथ सम्बन्धित होने का बोध कराता है। यह सिविल प्रशासन और स्वतः चैतन्य देशभक्ति के गठबन्धन की अपेक्षा करता है। राष्ट्र-राज्य अपने उन नागरिकों की आशाओं और महत्त्वाकांक्षाओं को मूर्त्त रूप देता है जो उसमें निष्ठा रखते हैं।

28.4.1 राज्य की परिभाषा और अर्थ

समाजशास्त्रियों के बीच एक व्यापक करार हुआ है कि राज्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाए। संयुक्त परिभाषा में तीन घटक शामिल होंगे। प्रथम, राज्य संस्थाओं का एक समूह है, जिसकी राज्य के निजी कर्मचारियों द्वारा व्यवस्था की जाती है। राज्य की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संस्था हिंसा और प्रपीड़न पर काबू पाने के साधनों की संस्था है। दूसरे, ये संस्थाएँ भौगोलिक रूप से घिरे हुए क्षेत्र के मध्य में हैं, जिसका आमतौर पर एक समाज के रूप में हवाला दिया जाता है। निर्णायक तौर पर, राज्य आन्तरिक रूप से अपने उन राष्ट्रीय समाज तथा बाह्य रूप से उन विशाल समाजों की ओर देखता है जिनके बीच उसे मार्ग तय करना चाहिए; प्रायः एक क्षेत्र में उसका व्यवहार दूसरे क्षेत्र में उसके क्रियाकलापों द्वारा समझाया जा सकता है। तीसरे, राज्य का अपने क्षेत्र के भीतर कानून बनाने का एकाधिकार होता है, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। यह सभी नागरिकों द्वारा सहयोजित एक साझा राजनीतिक संस्कृति के गठन के प्रति अभिमुख होती है।

28.4.2 संप्रभुता

राज्य का कानून/ नियम बनाने का अनन्य अधिकार प्रायः संप्रभुता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक विश्व और सम्पूर्ण शक्तिशाली राष्ट्र-राज्य के विकास में संकल्पना की धारणा

एक प्रमुख/मूल विचार है। आरंभ में, व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधिमान्य हिंसा करना स्पष्टतः राज्य का अधिकार था। परन्तु धीरे-धीरे संप्रभु राष्ट्र-राज्य ने सामाजिक न्याय जैसी संकल्पना अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर शामिल करके अनन्य प्राधिकार के ऊपर और अधिक विधिमान्य दावे किए। इस प्रकार, नागरिकों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने राष्ट्र-राज्यों की क्षमता से उम्मीदें विकसित की हैं। प्राधिकार लागू करने में उद्देश्य परकता राष्ट्र-राज्यों के कार्यों को वैधता प्रदान करती है। राज्य स्वायत्त और संप्रभु होता है, और एक प्रदत्त राष्ट्रीय समाज में सार्वभौमिक प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करता है।

28.4.3 संप्रभुता को खतरा

तथापि, राष्ट्र-राज्य बीसवीं शताब्दी के अंत में वैश्वीकरण के आने से संकटपूर्ण स्थिति में फँस गया है, क्योंकि राष्ट्र-राज्य की स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को भूमण्डलीय स्तर पर बाह्य बलों द्वारा तथा स्थानीय स्तर पर आन्तरिक बलों द्वारा क्षति पहुँचाई गई है। इसने राष्ट्र-राज्य की तरह उसके अस्तित्व के बहु-आयामी होने की वैधता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया। राष्ट्र-राज्य भूमण्डलीय समेकन और स्थानीय विघटन के बलों द्वारा बीचों बीच फँसा लिए गए हैं।

लोगों के जीवन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रिश्ते की रचना राष्ट्र-राज्य के साथ उनका सम्बन्ध है। राष्ट्र, लोग जिनके अब तक राज्यों के साथ विशेषाधिकारपूर्ण सम्बन्ध थे, के पास ऐसे सम्बन्ध अब नहीं रहे क्योंकि राज्य निजी तौर पर न तो भूमण्डलीय शक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए सक्षम है और न वे अपने उन नागरिकों के मध्य एकता का बोध कायम करने की स्थिति में हैं, जो अनन्य पहचान बनाकर रहना चाहते हैं। तृतीय विश्व के देश इसे अधिक गंभीरता से महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों सीमाओं पर राज्यों की (अ) योग्यता अधिक प्रबल है। नागरिक संगठनों के नए स्वरूप तलाश कर रहे हैं, जिनमें विभिन्न तरीकों से उनकी पहचान/अस्तित्व के दावे अन्तर्ग्रस्त हैं। इसके प्रभाव कई गुने हैं। स्थानीय समुदाय जो अधिक संसाधनों की माँग कर रहे हैं, कभी-कभी देखेंगे कि उनके हित राष्ट्र-राज्यों का आश्रय लेने तथा किसी दूसरे समय उनका विध्वंश करने में अन्तर्निहित हैं। अन्तरराष्ट्रीय संगठन अधिक वैधता की माँग करेंगे और इसे सुनिश्चित करने का एक तरीका यह है कि समर्थक देशों की अपनी निजी वैधता है।

विश्व शिखरवार्ताओं की हाल की स्थिति में यह समझाना पड़ेगा कि स्थानीय समुदाय किस प्रकार सीमा पार की हस्तियाँ बनने की माँग कर रहें हैं। मानव अधिकार ग्रुपों की वियाना शिखरवार्ता, महिला ग्रुपों की बीजिंग शिखरवार्ता, पारिस्थितिकी ग्रुपों की रियो शिखरवार्ता, जातिवाद के विरुद्ध डरबन शिखरवार्ता अथवा विश्व समाज फोरम, सभी प्रजाति, जाति, लिंग, पारिस्थितिक मुद्दों के आधार पर राष्ट्र की सीमाओं से परे स्थानीय समुदायों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत हैं। वे राष्ट्र-राज्यों के दायरे से परे सामाजिक न्याय का प्रश्न उठाते हैं, और उन्हें भूमण्डलीय प्रक्रिया से जोड़ते हैं। उदाहरणार्थ, मानव अधिकारों को किसी देश के भीतर आकर्षक रिकॉर्ड किसी उधार देने वाली भूमण्डलीय एजेंसी अथवा दाता एजेंसी से ऋण, सहायता अनुदान लेने के योग्य बनने के लिए काफी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार के रिकॉर्ड अन्तरराष्ट्रीय उधारी संव्यवहारों में एक निर्णायक मुद्दे के रूप में छाए हुए हैं। इससे पता चलता है कि राष्ट्र-राज्य किस प्रकार घरेलू और भूमण्डलीय ताकतों दोनों से कितना अधिक दबाव में है।

बोध प्रश्न 3

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिये अंत में देखें।

1) अपने निजी शब्दों में राज्य की परिभाषा दें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) वैश्वीकरण के मद्देनज़र राज्य संप्रभुता के ख़तरों से अवगत कराएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

28.5 वैश्वीकरण, राज्य और बहुराष्ट्रीय निगम

उत्पादन, वित्तपोषण और वाणिज्य के क्षेत्र में भूमण्डलीय एकता सर्वाधिक दृश्यमान है। राष्ट्रीय सीमाओं से परे कार्यरत बहुराष्ट्रीय निगम (MNCs) भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था को आधिकाधिक प्रभावित कर रहे हैं। मानकतावादी फैक्टरी-संकेन्द्रित उत्पादन जिसे राष्ट्र-राज्यों की संरक्षणात्मक नीतियों के आधार पर अपनाया गया था, से भिन्न, विद्यमान वित्तीय क्रियाकलाप जिसे मानकतावाद के बाद के विशिष्टगुण युक्त बताया गया है, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा नियंत्रित हैं। आरंभिक अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के असफल हो जाने से तथा तत्पश्चात् असमंजन, निजीकरण और उदारीकरण के आधार पर नई-उदारवादी सोच की भूमण्डलीय स्वीकृति हो जाने से, अन्तिम तीन दशकों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का वस्तुतः प्रसार हुआ है।

समसामयिक द्राक्षा संचयन (contemporary visage) का वैश्वीकरण सर्वाधिक दृश्यमान है और इसकी मीडिया तथा आर्थिक मोर्चे पर घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या का एक महत्त्वपूर्ण और वर्धमान क्षेत्र भूमण्डलीय बाजार में समेकित हो

रहा है। वित्तीय बाजार और पूँजी प्रवाह अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं के पार जाने की स्थिति में हैं तथा इच्छामात्र से संप्रभु राज्य के नियंत्रणों को तोड़ सकते हैं। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार भूमण्डलीय उत्पादन के 20 प्रतिशत के बराबर है और प्रतिवर्ष लगभग 5 खरब डॉलर अनुमानित है। सीमा पार के संव्यवहार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों (FDIs) और बहुराष्ट्रीय निगमों का महत्त्व राष्ट्रों के आर्थिक भाग्य का अवनिर्धारण करने में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है और इसका अधिकांश, राज्य नियंत्रण के अनुकूल नहीं है।

पाँच सौ उत्कृष्ट अन्तरराष्ट्रीय कम्पनियाँ भूमंडलीय उत्पादन के एक विशाल और वर्धमान हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2000 में पाँच सौ उत्कृष्ट निगमों के क्षेत्रीय वितरण से एक रोचक प्रवृत्ति का पता चलता है। निगमों की अधिकांश संख्या (56) बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। इससे हाल के वर्षों में अन्तरराष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या और वित्तीय पूँजी में चमत्कारिक वृद्धि का स्पष्टतः पता चलता है। वित्तीय क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश की युक्तिसंगतता स्पष्ट है, अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक निवेश की तुलना में भूमण्डलीय वित्तीय बाज़ारों में सट्टेबाजी (अव्यवहारिक) निवेशों से त्वरित लाभ उठाया जा सकता था। जहाँ तक बहुराष्ट्रीय निगमों का सम्बन्ध है, पेट्रोलियम शोधन, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, खाद्य और औषधि भंडार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बैंकों का अनुसरण करते हैं।

बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा वर्धमान आर्थिक आधिपत्य ने भूमण्डलीय पैमाने पर निगमित शासन की स्थापना की है। यद्यपि बहुराष्ट्रीय निगम राष्ट्र-राज्य संप्रभुता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते जैसा कुछ क्षेत्रों में विचार किया गया है, यह निश्चित रूप से इन राज्यों के समक्ष, विशेषकर विकासशील और अविकसित देशों में नीति विकल्पों को मूर्त्त रूप दे रहे हैं। बहुराष्ट्रीय निगम अभी भी इन राष्ट्रों में अपनी प्रविष्टि के लिए राज्यों से निर्णय लेने की अपेक्षा करते हैं। राज्य को इन राष्ट्रों में इन बहुराष्ट्रीय निगमों के सुगम संव्यवहार के लिए सुविधाएं मुहैया करानी पड़ती है और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करनी पड़ती है। निजी तौर पर, भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था का अपने पक्ष में मोड़े देने के लिए न तो उनके पास शक्ति है और न क्षमता। अपितु, बहुराष्ट्रीय निगम समसामयिक भूमंडलीय अर्थव्यवस्था को मूर्त्त रूप देने के लिए राष्ट्र-राज्यों और अन्तरराष्ट्रीय शासकीय संगठनों के समर्थन की माँग करते हैं।

28.6 वैश्वीकरण, राज्य और क्षेत्रीयता

आर्थिक उदारवाद के प्रति इस प्रत्यक्ष परिवर्तन के राजनीतिक सिद्धांत कहीं अधिक जटिल बन रहे हैं। यदि 1980वें दशक के अन्तिम वर्षों में प्रमाणांक बाज़ारोन्मुख था, राजनीति में राष्ट्रवादी तनावों का बड़े पैमाने पर तथा विश्व अर्थव्यवस्था को समुचित रूप से प्रयुक्त व करने में संस्थाओं की कमज़ोरी का पुनः प्रवर्तन हुआ। नई राजनीतिक संरचनाओं जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे जा सके, के गठन के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। 1992 के अंत में यूरोपीयन संघ ने अपने बारह सदस्य देशों के भीतर एकमात्र बाज़ार की स्थापना की। इसके अतिरिक्त यह आर्थिक सहयोग के बुनियादी समर्थन से एक राजनीतिक संघ के गठन के लिए संघर्ष कर रहा है। दूरस्थ पूर्वी यूरोप की सरकारें उन योजनाओं पर विचार कर रही हैं जो, बढ़ते हुए आर्थिक गठबंधन की तरह क्षेत्र के भीतर राजनीतिक सहयोग में वृद्धि करें। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका कनाडा और मेक्सिको के साथ मुक्त व्यापार करार स्थापित हो चुका है, अब एफ.टी.ए. (FTA) की संकल्पना को दक्षिण अमेरिका में लागू करने के लिए तैयार है।

हाल के वर्षों में दक्षेस देशों के अनुभव से हम जितना जानते हैं, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार (SAFTA) इन देशों की ओर से, उनके बीच मतभेदों के बावजूद और विशेष रूप से इससे भी अधिक, पाकिस्तान और भारत के बीच शत्रुता, एक बाध्यकारी प्रयोग बन गया है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार दक्षिण एशिया के मौद्रिक संघ से भी एक कदम आगे है। यह तथ्य कि देशों के मौद्रिक संघ की संभावना पर इस्लामाबाद में जनवरी, 2004 में आयोजित दक्षेस शिखरवार्ता में गंभीरता से विचार किया गया है, इस बात का सूचक है कि दक्षेस किस दिशा में जाना चाहता है।

इन व्यापारिक गठजोड़ों को राजनीतिक रूप देने के लिए प्रयास किए जाएँगे। विकसित और विकासशील देशों के बीच इन उदारवादी सिद्धांतों को लागू करने के प्रयास क्षेत्रीय आर्थिक निकायों की अन्यथा व्याप्ति (emergence) को आसान बना देंगे। ये क्षेत्रीय निकाय उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था के अनुरूप बहुराष्ट्रीय राजनीतिक भ्रूण के रूप में देखे जा सकते हैं।

बोध प्रश्न 4

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिये अंत में देखें।

1) वैश्वीकरण के संदर्भ में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका की विवेचना करें।

.....

.....

.....

.....

.....

28.7 वैश्वीकरण और द्वैतवाद (Dualism)

वैश्वीकरण का विभिन्न प्रकार के हित रखने वाले ग्रुपों द्वारा इतना अधिक प्रतिरोध क्यों हो रहा है? इनमें सबसे आगे पर्यावरणवादी, श्रमिक नेता, सांस्कृतिक परम्परावादी, विभिन्न आग्रहों वाले धार्मिक नेता और ग़ैर-सरकारी संगठन हैं। इससे बढ़ते हुए विरोध के बावजूद, पश्चिम के नेतृत्व और उसकी आर्थिक सम्पन्नता के साथ वैश्वीकरण असीमित गति से आगे बढ़ रहा है।

वैश्वीकरण में औद्योगिक क्रांति के बाद सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धों का सर्वाधिक मौलिक विकेन्द्रीकृत पुनर्गठन अंतर्गृस्त है। फिर भी इन परिवर्तनों के गंभीर निहितार्थ शायद ही कभी गंभीरता से सार्वजनिक संवीक्षा अथवा बहस के लिए सामने लाए गए हों। विश्व की बड़े पैमाने पर पुनर्व्यवस्था के बावजूद, न तो विश्व के नेताओं, न शैक्षणिक संस्थाओं और न विशाल मीडिया ने कभी यह जानने के लिए कि जिसका सूत्रपात हो रहा है अथवा, विशेष रूप से विकासशील देशों पर इसके प्रभावों की बहुआयामिता का पता लगाने के लिए भी कोई विश्वस्त प्रयास किए हैं।

विगत दशक में, हम अप्रत्याशित घटनाओं की एक शृंखला के साक्षी रहे हैं : शीत युद्ध का अंत, बाज़ार में महत्त्वाकांक्षी सुधार जिन्हें पहले अर्थव्यवस्थाओं के रूप में नियोजित किया

गया था; और पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा पूर्व एशिया में आर्थिक समेकन की प्रक्रिया और अधिकांश प्रमुख विक्रेताओं द्वारा संरक्षणवादी उपायों के बढ़ते हुए प्रयोग (विशेष रूप से विकासशील देशों के विरुद्ध औद्योगीकरण के बाद प्रगतिशील देशों द्वारा) की गति में तीव्रता लाना।

इसका मूल सिद्धांत प्रतिनिधिक आर्थिक वृद्धि की निरपेक्ष प्राथमिकता और अनियंत्रित मुक्त व्यापार के इर्द-गिर्द घूमता है, जिससे वृद्धि में गति लाने के लिए मुक्त व्यापार किया जा सके। मुक्त व्यापार निर्यात प्रतिस्थापना के उन अवरोधों को हटा देता है, जो आर्थिक स्वयं-संतुष्टि की प्रोन्नति के लिए अभिमुख होते हैं। यह लोक उद्यमों के त्वरित निजीकरण तथा उपभोक्तावाद की आक्रामक प्रोन्नति वाली निर्यात-आयात मूलक अर्थव्यवस्थाओं का पक्षधर है, जो भूमण्डलीय विकास के संयोजित किए जाने पर पाश्चात्य दर्शन को सही अर्थों में प्रतिबिम्बित करता है। इससे भी अधिक नए अन्तरराष्ट्रीय ढाँचे का नियामक सिद्धांत यह भी कल्पना करता है कि सभी देश तथा वे देश भी जिनकी संस्कृतियाँ उतनी विविध हैं जितनी मिश्र, भारत, चीन, इण्डोनेशिया, जापान, कोरिया, स्वीडन और ब्राज़ील की, कुछ अन्य देशों के साथ, अब अपनी उभरती हुई नौकाओं को एक साथ मिलकर चलाते हैं। इस प्रक्रिया का निबल परिणाम उन शक्तिशाली देशों को उन्मुक्त करना है, जो उत्पादों और सेवाओं में एक पाश्चात्य सांस्कृतिक एकरूपता की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण विकासशील राष्ट्रों के ऊपर स्थानीय परम्पराओं को छोड़ने के लिए निरन्तर दबाव बनाए रखेगा तथा और अधिक स्वतः तुष्ट अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए तत्पर कार्यक्रमों को विखंडित करेगा।

पश्चिम से इस प्रकार के दबाव का एक अच्छा उदाहरण बांग्लादेश है। बांग्लादेश में, बैंकिंग का निजीकरण कर दिया गया है और यह देश बीमा क्षेत्र में अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रहा है। बैंक जो आरंभ में ज़रूरतमंद और ग्रामीण क्षेत्र की सहायता के स्पष्ट प्रयोजनार्थ राष्ट्रीयकृत किए गए थे, निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं।

विकासशील देशों के लिए वैश्वीकरण को अनिश्चितता के साथ आलिंगनबद्ध करना संकटपूर्ण हो चुका है। इसके नकारात्मक परिणामों की चर्चा कभी-कभार की जाती है। इसकी बजाए, आर्थिक विकास में कमी के लिए विशेष प्रकार से कुशासन, भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण व्यवहार दोषी है। वैश्वीकरण के विचार की अन्धी स्वीकृति विकासशील देशों के नज़रिए से अस्वीकार्य, नैसर्गिक और सर्वथा भयानक है।

28.7.1 विश्व का दो कैम्पों में विभाजन

वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व के दो कैम्पों में विभाजन के लिए अग्रसर है। पश्चिम का तर्क है कि वैश्वीकरण का लाभ व्यापक है और इससे विकसित और विकासशील, दोनों राष्ट्रों को लाभ होता है। विकासशील देश वैश्वीकरण को अधिक संदेह की दृष्टि से देखते हैं। यदि नहीं, तो अनपेक्षित दोषदर्शिता बनी रहती है। हमें वैश्वीकरण पर उनकी सापेक्ष स्थितियों पर विचार करना चाहिए।

वैश्वीकरण के लाभों हेतु पश्चिमी दावे इस प्रकार हैं : यह (1) संस्थागत तथा व्यक्तिगत विकास दोनों प्रकार के विकास के लिए प्रचुर पूँजी निवेश मुहैया कराता है। (2) विकासशील देशों के नागरिकों को रोज़गार के बढ़े हुए अवसर प्रदान करता है (3) शिक्षा के माध्यम से जन समुदाय के कल्याण के लिए सुधार की संकल्पनाओं में वृद्धि करता है। (4) अवस्थापना विकास को गति प्रदान करता है जैसे, सड़कें, शक्ति संयंत्र और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार। (5) प्रगतिशील राष्ट्रों द्वारा विकासशील देशों को बिना किसी लागत के प्रौद्योगिकी

की व्यवस्था करता है। इस प्रक्रिया से संभवतः सार्वभौमिक तौर पर कार्यकारी शर्तें, मानक, अभिवृत्तियाँ और मूल्य समान हो जाएँगे।

इसके प्रतिकूल, विकासशील देशों का तर्क है कि वैश्वीकरण वचनबद्धता के मुकाबले प्रचुरता से काफी कम मुहैया करा रहा है। उनके अनुसार : (1) वैश्वीकरण ने विकासशील देशों को उनके द्वारा इन देशों में किए गए निवेश की अपेक्षा लाभों से अधिक धन लिए जाने के कारण पूँजी रहित कर दिया है। (2) निवेश में पूँजी अधिक लगाने की बजाए, कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ स्थानीय देनदारों से उधार लेती हैं और इस प्रकार उन दुर्लभ पूँजी संसाधनों का क्षय कर रहीं हैं, जिन्हें देश के कारोबारियाँ द्वारा उपयोग में लाया जाना चाहिए। (3) नई प्रौद्योगिकियों से लाभों की वचनबद्धता संभवतया निकट भविष्य में निराशाजनक सिद्ध होगी, क्योंकि इसके कारण होने वाली निर्भरता से विकासशील देशों में नवीनीकरण अवरुद्ध हो जाता है। (4) वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय निगमों से विज्ञापन की एक बेहतरीन, परिष्कृत ब्राण्ड सामने आती है जो उपभोक्तावाद और विलास वस्तुओं के आयातीकरण को बढ़ावा देती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों और सेवाओं के विपणन में सफलता से घरेलू निवेशों जो घरेलू आर्थिक वृद्धि की जान हैं, में कमी आती है। (5) वैश्वीकरण में, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विदेशों में आर्थिक सहायता देकर व्यापार पर वाणिज्यिक प्रतिबन्धों का प्रतिकार कर सकती हैं। वास्तव में, यह उन्हें व्यापार अवरोधों पर काबू पाने, उत्पादन जारी रखने और विकासशील देशों की लागत पर लाभ कमाने की अनुमति देता है।

आज की तरह, उभरते हुए विश्व पूँजीवाद के किन्हीं पूर्ण विकल्पों के लिए बहुत ही कम आशा प्रतीत होती है। विश्व व्यापार संगठन जैसी बहुपार्श्वीय संस्थाओं के उभरने से, प्रत्येक देश वस्तुतः विश्व अर्थव्यवस्था में फँस गया है और धीरे-धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त कर रहा है। मैक्सिको जैसे देश जो एक दशक पहले राज्य के नियंत्रण और स्वामित्व पर विश्वास रखते थे, बुरी तरह से निजीकरण कर रहे हैं। थाइलैण्ड अपने बजट का संतुलन बना रहा है; पेरु टैरिफ दर कम कर रहा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भी देश, जिन्होंने नब्बे के दशक के प्रारम्भ में यद्यपि विलम्ब से शुरुआत की थी, उत्तरोत्तर उदारीकरण को अपनाए जा रहे हैं और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मुक्त कर रहे हैं। बीसवीं शताब्दी का आर्थिक उदारवाद निजी स्वामित्व, कारोबार में राज्य के लिए घटती हुई भूमिका, न्यूनतर व्यापार अवरोध, करों में कमी, और प्रदत्त आर्थिक व्यवस्था में सर्वाधिक दक्ष वितरक के रूप में बाज़ार पर आम विश्वास के लिए उत्तरदायी है।

वैश्वीकरण को समझने की समस्या उसके उस द्वैतवाद में सन्निहित है, जो विद्यमान अर्थ-व्यवस्था को नियंत्रित करता है। यदि वैश्वीकरण एकीकृत विश्व का हवाला देता है, यह भी उतना ही सत्य है कि विश्व दो असमय हिस्सों – गरीब और अमीर, *राष्ट्रों* में उत्तरोत्तर विभाजन की ओर अग्रसर है, जिसमें अधिक प्रगतिशील पाश्चात्य राष्ट्र तथाकथित मुक्त व्यापार और नई भूमण्डलीय व्यवस्था द्वारा वकालत की गई मुक्तता का लाभ उठा रहे हैं। राष्ट्रीय सीमाओं का भेदन उन्नत देशों के पक्ष में कार्य कर रहा है। इस दुवृत्त अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न देशों के लिए भिन्न-भिन्न निहितार्थ हैं। कई गहन अध्ययनों से पता चलता है कि असमानता और न्याय के मुद्दे उभरती हुई भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक चिन्ता का विषय बनने जा रहे हैं।

जैसी कि ऊपर चर्चा की गई थी, वैश्वीकरण ने राष्ट्र-राज्यों को, विशेष रूप से तृतीय विश्व में, आर्थिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित किया है। पश्चिम के वर्चस्व में अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार व्यापार की शर्तों पर बातचीत करने के लिए दक्षिण देशों (गरीब देशों का पर्यायवाची) के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है। यद्यपि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के

क्रियाकलाप सीमाओं से परे हैं, तथापि उनके हित आज भी उनके पैत्रिक देशों से जुड़े हुए हैं जो अक्सर उन्नत पश्चिमी देश हैं। बहुराष्ट्रीय निगम अपने हितों में इतने बहुराष्ट्रीय नहीं हैं।

सूचना युग के आने से, विश्व सिकुड़कर जैसा कि मार्शल मैकलुहान ने कहा है, एक भूमण्डलीय गाँव बन गया है जहाँ राजनीतिक और सांस्कृतिक अर्थों में, राष्ट्रीय सीमाओं में और अधिक रन्ध्र (porous) हो गए हैं। इस प्रकार, और अधिक पराजेय तृतीय विश्व पर पश्चिम द्वारा राजनीतिक और सांस्कृतिक घातक प्रहारों के बारे में इससे और अधिक व्यग्रता तथा सजीव चिन्ताएँ प्रस्तुत होती हैं। नई सूचना के साथ संयोजित होकर भूमण्डलीय आर्थिक व्यवस्था से उन्नत देशों में राष्ट्र-राज्य को मज़बूत होने तथा तृतीय विश्व में राज्य के कमज़ोर होने की संभावना है। यह द्वैतवाद और विरोधाभास उभरती हुई भूमण्डलीय व्यवस्था में राष्ट्र-राज्य को विशिष्ट लक्षण देने जा रहे हैं।

बोध प्रश्न 5

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिये अंत में देखें।

1) विकसित और विकासशील राष्ट्रों के संदर्श से वैश्वीकरण की विवेचना करें।

.....

.....

.....

.....

.....

28.8 एक मूल्यांकन

भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राष्ट्र-राज्य की संप्रभुता के सापेक्ष पतन से प्रमुखतः तृतीय विश्व के देशों में जहाँ राज्य की अपेक्षाएँ बहुत उत्कृष्ट हैं तथा राज्य की क्षमताएँ कम हैं, एक लोकतांत्रिक पराभव (deficit) पैदा हो रहा है। नागरिक उन मुद्दों पर जिनके ऊपर राज्य का कोई स्वायत्त नियंत्रण नहीं है, अपनी राष्ट्रीय सरकारों को उत्तरदायी बनाए हुए हैं। अपने नागरिकों द्वारा वाहित निष्ठा के प्रति प्रबल बोध जो उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष से विकसित हुआ, राष्ट्रीय सरकारों की स्वायत्तता के पतन के अनुरूप कमज़ोर नहीं हुआ है। 'भूमण्डलीय गाँव' के आगमन के बावजूद व्यष्टि अभी तक उभरते हुए परमराष्ट्रीय निकायों जैसे 'यूरोपीयन संघ' के प्रति बहुत कम निष्ठा महसूस करते हैं। यह कुल मिलाकर ऐसे परमराष्ट्रीय निकायों के प्रति दक्षिण में नागरिकों की सम्बद्धता की और अधिक दूरगामी उम्मीद है। इसी प्रकार, एक राष्ट्र के भीतर राज्य की तरह नागरिकों की वफादारी पर भलीभाँति नियंत्रण रखने के लिए उभरती हुई पहचानों की कल्पना करना कठिन है। फिर भी हम देख सकते हैं कि तृतीय विश्व में लोकतांत्रिक पराभव बड़े पैमाने पर तनाव पैदा करने जा रहा है। वैश्वीकरण पश्चिम की अपनी अन्याय व्यवस्था की तुलना में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुकाबलों पर तृतीय विश्व पर और अधिक कष्टकारी तनाव कायम रखता है।

भूमण्डलीय प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप न तो राष्ट्र और न ही राज्य गायब होने वाले हैं। शुरुआती तौर पर ऐसी कोई प्रतिस्थानी संरचना नहीं है, जो राष्ट्र-राज्य से जुड़े हुए सभी परम्परागत कार्यों को सम्पन्न कर सके। इसी के साथ लोक राज्य-संकेन्द्रित राष्ट्रीयवाद को पूर्णरूपेण छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीयवाद ऐतिहासिक रूप से अंतःस्थापित है और सांस्कृतिक रूप से अनुभव किया जाता है। फिर भी इसे नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि पहचान के लिए राज्य का विखंडन राष्ट्र-राज्य का प्रतिस्थायी नहीं हो सकता है। निष्ठा के अर्थ बदल रहे हैं और अनिवार्यतः परिणामस्वरूप विविध वफादारियाँ दृष्टिगोचर होगीं। निश्चित तौर पर, यद्यपि राष्ट्र-राज्य गायब नहीं होगा, परन्तु इस तरीके से नहीं होंगे जैसे ये अब हैं। नागरिकों की निष्ठा के स्वरूप और स्थितियों में बदलाव आएगा।

बोध प्रश्न 6

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिए इकाई का अंत देखें।

1) वैश्वीकरण की वर्तमान और भावी प्रकृतियों पर समालोचना लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

28.9 सारांश

इस इकाई में, आपने वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य के बारे में अध्ययन किया है। दोनों शब्दों की परिभाषा/अर्थ को समझाया गया है। भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक – को स्पर्श किया गया है। वैश्वीकरण की स्थिति में राज्य संप्रभुता की आशंकाओं पर इस इकाई में विस्तार से चर्चा की गई है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। इस इकाई में, वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप विश्व के दो कैम्पों में बँट जाने के निहितार्थों का भी उल्लेख किया गया है। आशा की जाती है कि अब आप शब्द वैश्वीकरण को उसके अनेक सूक्ष्म भेदों, विशेष रूप से आधुनिक राज्य के साथ उसके अन्तरसंबंध को भलीभाँति समझ पाएँगे।

28.10 कुछ उपयोगी संदर्भ

अप्पादोराई, अर्जुन, *माडर्निटी एट लार्ज* : कल्चरल डाईमेन्शन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मिनियापोलिज़, मिनेसोट्टा, 1996।

गिडेन्स, ऐन्थनी, *कॉन्सेक्यून्सेन्स ऑफ मॉडर्निटी*, कैम्ब्रिज, पॉलिटी, 1990

28.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) देखें भाग 28.2

बोध प्रश्न 2

1) देखें उप-भाग 28.3.1 और 28.3.2

2) देखें उप-भाग 28.3.3

बोध प्रश्न 3

1) देखें उप-भाग 28.4.1

2) देखें उप-भाग 28.4.2 और 28.4.3

बोध प्रश्न 4

1) देखें भाग 28.5

बोध प्रश्न 5

1) देखें भाग 28.7 एवं उप-भाग 28.7.1

बोध प्रश्न 6

1) देखें भाग 28.8